



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 14 फरवरी, 2019 / 25 माघ, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 फरवरी, 2019

संख्या:एफ.एफ.ई.-बी.-एफ(2)8 / 2017(I).—संसद द्वारा पारित, "प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38)" भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 3 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किया गया है।

2. केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या: एस0ओ0 3967 (ई) तारीख 13 अगस्त, 2018 द्वारा 30 सितम्बर, 2018 को ऐसा दिन नियत किया है जिसको उक्त अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे;

3. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10 की उप-धारा (1) उपबन्धित करती है कि:-

‘उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, प्रत्येक राज्य में ‘हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण’ के नाम से ज्ञात एक राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा’;

4. केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या: का.आ. 4856 (अ) तारीख 14-09-2018 द्वारा “हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” के नाम से ज्ञात राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख 30 सितम्बर, 2018 नियत की है।

5. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से हिमाचल प्रदेश राज्य में “हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘राज्य प्राधिकरण’ कहा गया है) का गठन करते हैं।

6. राज्य में गठित राज्य प्राधिकरण प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के प्रबंधन और प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 के उपबन्धों के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (रा०प्र०व०नि०) इसके उपयोग के लिए दायी होगा।

7. राज्य प्राधिकरण शासी निकाय से गठित होगा और विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति द्वारा इसकी सहायता की जाएगी।

8. राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्:-

(i)	राज्य का मुख्य मन्त्री	..	पदेन अध्यक्ष;
(ii)	वन मन्त्री	..	पदेन सदस्य;
(iii)	मुख्य सचिव	..	पदेन सदस्य;
(iv)	प्रधान सचिव (पर्यावरण)	..	पदेन सदस्य;
(v)	प्रधान सचिव (वित्त)	..	पदेन सदस्य;
(vi)	प्रधान सचिव (योजना)	..	पदेन सदस्य;
(vii)	प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)	..	पदेन सदस्य;
(viii)	प्रधान सचिव (राजस्व)	..	पदेन सदस्य;
(ix)	प्रधान सचिव (कृषि)	..	पदेन सदस्य;
(x)	प्रधान सचिव (जनजातीय विकास)	..	पदेन सदस्य;
(xi)	प्रधान सचिव (पंचायती राज)	..	पदेन सदस्य;
(xii)	प्रधान सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	..	पदेन सदस्य;
(xiii)	प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल का प्रमुख)	..	पदेन सदस्य;
(xiv)	मुख्य वन्य जीव वार्डन	..	पदेन सदस्य; और
(xv)	प्रधान सचिव (वन)	..	सदस्य सचिव।

9. राज्य प्राधिकरण का शासी निकायः—

(i) राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित मूलभूत पद्धति (ढांचे) के भीतर राज्य प्राधिकरण के कार्यकरण के लिए व्यापक नीति मूलभूत पद्धति (ढांचा) अधिकथित करेगा;

(ii) राज्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली का समय—समय पर पुनर्विलोकन करेगा।

10. राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय कम से कम छह मास में एक बार बैठक करेगा।

11. राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों और शक्तियों के पालन में विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति द्वारा सहायता की जाएगी।

12. राज्य प्राधिकरण का शासी निकाय, विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति को इसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति से राज्य प्राधिकरण में सहायक अरण्यपाल और अन्य कर्मचारियों के स्तर पर पदों का सृजन कर सकेगा।

13. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:—

(i) मुख्य सचिव	..	पदेन अध्यक्ष;
(ii) प्रधान सचिव (वन)	..	पदेन सदस्य;
(iii) प्रधान सचिव (पर्यावरण)	..	पदेन सदस्य;
(iv) प्रधान सचिव (वित्त)	..	पदेन सदस्य;
(v) प्रधान सचिव (योजना)	..	पदेन सदस्य;
(vi) प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)	..	पदेन सदस्य;
(vii) प्रधान सचिव (राजस्व)	..	पदेन सदस्य;
(viii) प्रधान सचिव (कृषि)	..	पदेन सदस्य;
(ix) प्रधान सचिव (जनजातीय विकास)	..	पदेन सदस्य;
(x) प्रधान सचिव (पंचायती राज)	..	पदेन सदस्य;
(xi) प्रधान सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	..	पदेन सदस्य;
(xii) प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल का प्रमुख)	..	पदेन सदस्य;
(xiii) मुख्य वन्य जीव वार्डन	..	पदेन सदस्य;
(xiv) नोडल अधिकारी, वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980	..	पदेन सदस्य;
(xv) प्रमुख, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, देहरादून	..	पदेन सदस्य;
(xvi) नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभियान	..	पदेन सदस्य;
(xvii) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है	..	सदस्य; और
(xviii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण	..	सदस्य सचिव।

14. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति:-

- (i) राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति द्वारा तैयार की गई संक्रियाओं की वार्षिक योजना की संवीक्षा और ऐसे संशोधनों के साथ, जिन्हें वह ठीक और उचित समझती है, अनुमोदन करेगी और उसे अन्तिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति को भेजेगी;
- (ii) राज्य निधि से जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति को मॉनीटर करेगी;
- (iii) कार्यपालक समिति द्वारा किए गए विनिश्चयों सम्बन्धी रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करेगी;
- (iv) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए कार्यपालक समिति द्वारा निश्चित किए गए प्रस्तावों का राज्य सरकार की पूर्व सहमति के अध्यधीन अनुमोदन करेगी;
- (v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी और उसे प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए राज्य सरकार को भेजेगी;
- (vi) अन्तर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करेगी।

15. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

16. राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:-

(i) प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन बल का प्रमुख)	..	पदेन अध्यक्ष;
(ii) मुख्य वन्य जीव वार्डन	..	पदेन सदस्य;
(iii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वित्त)	..	पदेन सदस्य;
(iv) अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	..	पदेन सदस्य;
(v) नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण	..	पदेन सदस्य;
(vi) पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(vii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(viii) योजना विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(ix) ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(x) राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(xi) कृषि विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(xii) जनजातीय विकास विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(xiii) पंचायती राज विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(xiv) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि	..	पदेन सदस्य;
(xv) वित्त विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वित्त नियन्त्रक या वित्तीय सलाहकार	..	पदेन सदस्य;
(xvi) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो विष्यात गैर-सरकारी संगठन	..	सदस्य;
(xvii) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले जिला स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के दो प्रतिनिधि	..	सदस्य;

(xviii) जनजातीय विषयों का एक विशेषज्ञ या जनजातीय समुदायों का एक प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है . . . सदस्य; और

(xix) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण . . . सदस्य, सचिव

17. राज्य प्राधिकरण की कार्यपालक समिति :—

- (i) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति की सहमति अभिप्राप्त करने के लिए संक्रियाओं की वार्षिक योजना तैयार करेगी और उसे राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी;
- (ii) राज्य निधि में उपलब्ध रकम से कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों की गुणात्मक और परिमाणात्मक पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करेगी;
- (iii) लेखा बहियां और अन्य अभिलेख अनुरक्षित करेगी;
- (iv) राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;
- (v) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी;
- (vi) राज्य प्राधिकरण में पदों पर संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी अभिनियोजित करेगी;
- (vii) राज्य प्राधिकरण में पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी;
- (viii) वित्तीय या प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उत्तरदायी होगी;
- (ix) राज्य प्राधिकरण के सम्बन्ध में दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगी;
- (x) राज्य प्राधिकरण की जन सूचना प्रणाली बनाए रखेगी और उसे अद्यतन करेगी और लोकाधिकारी क्षेत्र उसके संव्यवहार से सम्बन्धित सभी सूचनाएं प्रस्तुत करेगी;
- (xi) ऐसे कोई अन्य कार्य करेगी, जो राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय या विषय निर्वाचन समिति या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं।

18. राज्य प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

19. राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और उसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

20. राज्य सरकार किसी अधिकारी, जो मुख्य अरण्यपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, को राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी।

21. राज्य प्राधिकरण अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के पालन में विषय निर्वाचन समिति तथा कार्यपालक समिति की सहायता के लिए पांच वर्ष से अनीधिक अवधि के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी, अर्थात्:—

- (i) संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो अरण्यपाल की पंक्ति से नीचे का न हो;

- (ii) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;
- (iii) उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो उप अरण्यपाल की पंक्ति से नीचे का न हो।

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(2)8/2017(I) dated 04-02-2019 required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 4th February, 2019

No. FFE-B.F(2)8/2017(I).—Whereas “The COMPENSATORY AFFORESTATION FUND ACT, 2016 (38 of 2016)”, passed by the Parliament, has been published by the Government of India in the Gazette of India, Extraordinary on 3rd August, 2016.

2. AND whereas the Central Government *vide* notification No. S.O. 3967(E) dated 13th August 2018, has appointed the 30th day of September 2018 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

3. AND whereas sub-section (1) of Section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act 2016 (38 of 2016) provides that:—

“With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, there shall be constituted a State Authority to be called the ‘State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority’ in each State;”

4. AND whereas the Central Government, *vide* notification No. S.O. 4856(E) dated 14-09-2018, has appointed the 30th day of September 2018 as the date of constitution of the State Authority to be called “The Himachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority”.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute “The Himachal Pradesh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority” (hereinafter refer to as the 'State Authority') in the State of Himachal Pradesh, for the purposes of this Act, with effect from the date of its publication in the official gazette.

6. The State Authority constituted in the State shall be responsible for the management of the State Compensatory Afforestation Fund (SCAF) of Himachal Pradesh and its utilisation as per the provisions of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 and the Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018.

7. The State Authority shall consist of a Governing Body and shall be assisted by a Steering Committee and an Executive Committee.

8. The Governing Body of the State Authority shall consist of the following, namely:—

(i) Chief Minister of the State	..	Chairperson, ex officio;
(ii) Minister of Forests	..	Member, ex officio;
(iii) Chief Secretary	..	Member, ex officio;
(iv) Principal Secretary (Environment)	..	Member, ex officio;
(v) Principal Secretary (Finance)	..	Member, ex officio;
(vi) Principal Secretary (Planning)	..	Member, ex officio;
(vii) Principal Secretary (Rural Development)	..	Member, ex officio;
(viii) Principal Secretary (Revenue)	..	Member, ex officio;
(ix) Principal Secretary (Agriculture)	..	Member, ex officio;
(x) Principal Secretary (Tribal Development)	..	Member, ex officio;
(xi) Principal Secretary (Panchayati Raj)	..	Member, ex officio;
(x) Principal Secretary (Science & Technology)	..	Member, ex officio;
(xi) Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	..	Member, ex officio;
(xii) Chief Wildlife Warden	..	Member, ex officio; and
(xiii) Principal Secretary (Forests)	..	Member Secretary.

9. The Governing Body of the State Authority shall :—

- (i) lay down the broad policy framework for the functioning of the State Authority within the overall framework notified by the Central Government on the recommendations of the National Authority;
- (ii) Review the working of the State Authority from time to time.

10. The Governing Body of the State Authority shall meet atleast once in six months.

11. The Governing Body of the State Authority shall, in performance of its functions and powers under the Act, be assisted by the Steering Committee and the Executive Committee.

12. The Governing Body of the State Authority may with the prior concurrence of the State Government create posts in the State Authority at the level of Assistant Conservator of Forests and other officials to assist the Steering Committee and Executive Committee in performance of its functions.

13. The Steering Committee of the State Authority shall consist of the following, namely:—

- (i) Chief Secretary .. Chairperson, ex officio;

(ii)	Principal Secretary (Forests)	.. Member, ex officio;
(iii)	Principal Secretary (Environment)	.. Member, ex officio;
(iv)	Principal Secretary (Finance)	.. Member, ex officio;
(v)	Principal Secretary (Planning)	.. Member, ex officio;
(vi)	Principal Secretary (Rural Development)	.. Member, ex officio;
(vii)	Principal Secretary (Revenue)	.. Member, ex officio;
(viii)	Principal Secretary (Agriculture)	.. Member, ex officio;
(ix)	Principal Secretary (Tribal Development)	.. Member, ex officio;
(x)	Principal Secretary (Panchayati Raj)	.. Member, ex officio;
(xi)	Principal Secretary (Science & Technology)	.. Member, ex officio;
(xii)	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	.. Member, ex officio;
(xiii)	Chief Wildlife Warden	.. Member, ex officio;
(xiv)	Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980	.. Member, ex officio;
(xv)	Head, Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Dehradun	.. Member, ex officio;
(xvi)	Nodal Officer, State Forest Development Agency	.. Member, ex officio;
(xvii)	An expert on tribal matters or a representative of tribal communities to be appointed by the State Government	.. Member; and
(xviii)	Chief Executive Officer, State Authority	.. Member-Secretary.

14. The Steering Committee of the State Authority shall :—

- (i) Scrutinise and approve with such amendments as it may deem fit and proper, the annual plan of operations prepared by the Executive Committee of the State Authority and send the same to the Executive Committee of the National Authority for final approval;
- (ii) Monitor the progress of utilisation of funds released from the State Fund;
- (iii) Review reports on decision taken by the Executive Committee;
- (iv) Approve, subject to prior concurrence of the State Government, proposals formulated by the Executive Committee for creation of posts in the State Authority;
- (v) Approve annual report of the State Authority and send the same to the State Government to lay it, each year, in each House of the State Legislature;
- (vi) Ensure inter-departmental coordination.

15. The Steering Committee of the State Authority shall meet atleast once in every three months.

16. The Executive Committee of the State Authority shall consist of the following, namely: —

(i)	Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force)	..	Chairperson, ex officio;
(ii)	Chief Wildlife Warden	..	Member, ex officio;
(iii)	Addl. Pr. Chief Conservator of Forests Finance.	..	Member, ex officio;
(iv)	Addl. Pr. Chief Conservator of Forests (Research & Training)	..	Member, ex officio;
(v)	Nodal Officer, State Forest Development Agency.	..	Member, ex officio;
(vi)	Representative, Department of Environment	..	Member, ex officio;
(vii)	Representative, Department of Finance	..	Member, ex officio;
(viii)	Representative, Department of Planning	..	Member, ex officio;
(ix)	Representative, Department of Rural Development	..	Member, ex officio;
(x)	Representative, Department of Revenue	..	Member, ex officio;
(xi)	Representative, Department of Agriculture	..	Member, ex officio;
(xii)	Representative, Department of Tribal Development	..	Member, ex officio;
(xiii)	Representative, Department of Panchayati Raj	..	Member, ex officio;
(xiv)	Representative, Department of Science and Technology	..	Member, ex officio;
(xv)	Financial Controller or Financial Adviser, to be nominated by the Finance Department	..	Member, ex officio;
(xvi)	Two eminent Non-Government Organisations to be appointed by the State Government	..	Members;
(xvii)	Two representatives of District Level Panchayati Raj Institutions to be appointed by the State Government	..	Members;
(xviii)	An expert on tribal matters or a representative of tribal community to be appointed by the State Government	..	Member; and

(xix) Chief Executive Officer, State Authority .. Member-Secretary.

17. The Executive Committee of the State Authority shall:—

- (i) Formulate and submit annual plan of operations to the Steering Committee of the State Authority for its concurrence;
- (ii) Undertake qualitative and quantitative supervision, monitoring and evaluation of the works being implemented from the amounts available in the State Fund;
- (iii) Maintain books of account and other records;
- (iv) Submit reports to the Steering Committee of the State Authority;
- (v) Prepare annual report of the State Authority;
- (vi) Deploy staff on contractual basis or on deputation on the posts in the State Authority;
- (vii) Formulate proposals for creation of posts in the State Authority;
- (viii) Be responsible for delegation of financial or administrative powers;
- (ix) Be responsible for other day-to-day working in respect of the State Authority;
- (x) Maintain and update public information system on the State Authority and present all information on its transaction in the public domain;
- (xi) Undertake any other work as may be assigned by the Governing Body or Steering Committee of the State Authority or the State Government, from time to time.

18. The Executive Committee of the State Authority shall meet at least once in every three months.

19. The State Authority shall prepare its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the State Authority and forward the same to the State Government and the Central Government in each financial year by 31st December.

20. The State Government shall appoint an officer not below the rank of a Chief Conservator of Forests as the Chief Executive Officer of the State Authority.

21. The State Authority may appoint the following officers for a period not exceeding five years, to assist the Steering Committee and Executive Committee in performance of its functions under the Act, namely:—

- (i) Joint Chief Executive Officer not below the rank of a Conservator of Forests;

(ii) Financial Advisor and Chief Accounts Officer not below the rank of a Deputy Secretary in the State Government;

(iii) Deputy Chief Executive Officer not below the rank of a Deputy Conservator of Forests.

By order,
 RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th February, 2019

No. TPT-A(4)-1/2019.—In supersession of this department notification of even number dated 18th January, 2013 issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of the power conferred by Section-3 of the H.P. City Transport Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (No. 18 of 1999) is pleased to reconstitute the H.P. City Transport Bus Stands Management and Development Authority with immediate effect in the public interest as follows:—

1. Hon'ble Transport Minister, Himachal Pradesh . . . *Chairman*
2. The Addl. Chief Secretary (PWD) to the Government of Himachal Pradesh . . . *Member*
3. The Principal Secretary (Tourism) to the Government of Himachal Pradesh . . . *Member*
4. The Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh . . . *Member*
5. Chief Executive Officer, Himachal Pradesh HP CT& BSMDA . . . *Member*
6. The Director, Institutional Finance, Himachal Pradesh . . . *Member*
7. The Director (Transport) Himachal Pradesh . . . *Member*
8. The Secretary, State Transport Authority H.P., Parivhan Bhawan Shimla-4 . . . *Member Secretary.*

By order,
 Sd/-
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th February, 2019

No. TPT-A(4)-1/2019.—In supersession of this department notification of even number dated 24th July, 2013 issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the power conferred by Section-3 of the H.P. City Transport Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (No.18 of 1999) is pleased to nominate the following Non-Official Member on the Board of H.P. City Transport Bus Stands Management and Development Authority with immediate effect in the public interest:—

1. Sh. Thakur Dass, VPO Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.)
2. Sh. Bihari Lal s/o Rootho Ram, VPO Cholthara, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).
3. Sh. Tara Chand Thakur, r/o Durga Medical Store, Recongpeo, Distt. Kinnaur (H.P.).
4. Sh. Amit Vaid, Advocate H.P. High Court Shimla, (H.P.)
5. CA Sh. Ravinder Kumar, r/o Near HPPWD Workshop Shamshi, Tehsil Bhunter, Distt. Kullu, (H.P.).
6. Sh. Chander Mohan Sharma, VPO Pingla, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi, (H.P.).

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Transport).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th January, 2019

No. HHC/Admn.3(390)/94-I.— 06 days earned leave *w.e.f.* 28-01-2019 to 02-02-2019, with permission to prefix Sunday on 27-01-2019 & suffix Sundays and 2nd batch special casual leave *w.e.f.* 03-02-2019 to 24-02-2019 is hereby sanctioned, in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th January, 2019

No. HHC/Estt.3(516)/2001-I.—06 days earned leave on and with effect from 28-01-2019 to 02-02-2019, with permission to prefix Sunday falling on 27-01-2019 and suffix Sundays, 2nd batch special casual leave commencing from 03-02-2019 to 24-02-2019, is hereby sanctioned, in favour of Shri Tilak Raj Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Tilak Raj Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th January, 2019

No. HHC/Admn.3(270)/88-I.—04 days commuted leave on and with effect from 12-12-2018 to 15-12-2018, with permission to suffix Sunday on 16-12-2018 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Sanjokta Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Sanjokta Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 12th February, 2019

No. GAD-C(F)10-2/2018.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a Cabinet Sub-Committee consisting of the following to examine the issue of providing 10% reservation to the Economically Weaker Sections (EWSs) other than backward classes in the services of the State in Class-I, II, III & IV posts in direct recruitment:—

1. Shri Suresh Bhardwaj, Education Minister.	<i>Chairman</i>
2. Dr. Ram Lal Markanda, Agriculture Minister.	<i>Member</i>
3. Shri Virender Kanwar, Rural Development Minister.	<i>Member</i>
4. Additional Chief Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh.	<i>Member-Secretary..</i>

The aforesaid Sub-Committee shall place the report before the Cabinet in its next meeting.

By order,

*B. K. AGARWAL,
Chief Secretary.*

[Authoritative English text of this Department Corrigendum No. EXN-F(10)-33/2018 dated 13-2-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 13th February, 2019

No. EXN-F(10)-33/2018.—In the notifications of the Government of Himachal Pradesh, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-33/2018, dated the 31st December, 2018 :

1. in the notification No. 24/2018-State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018 at page 7230, in line 10, *for “383A” read “383”*.
2. in the notification No. 26/2018-State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018:
 - (i) at page No. 7232, in the opening Para, in line 8 *for “Volume-1, to registered exporter of jewellery” read “to taxable person”*;

(ii) at page No. 7232, in the second Para, for “, Volume-I.” read “;” ;

(iii) at page 7233, for the explanation, the following explanation shall be read:

“Explanation.—for the purpose of this notification,—

(a) “Foreign Trade Policy ” means the Foreign Trade Policy, 2015- 2020, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* notification No. 41/2015-2020, dated the 5th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 3813, dated the 5th December, 2017;

(b) “Handbook of Procedures” means the Handbook of Procedure, notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry *vide* Public Notice No. 43/2015-2020, dated the 5th December, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC, dated the 5th December, 2017;

(c) “Nominated Agency” means entities mentioned in List 34 of Notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 published Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 sub- section (i), *vide* number G. S. R. 785 (E), dated the 30th June, 2017; (d) “Heading” means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”

By order,
Sd/-
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

[Authoritative English text of this Department Order No. EXN-F(10)-33/2018 dated 13-2-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER/ No. 1/2019-State Tax

Shimla-2 the 13th February, 2019

No. EXN-F(10)-33/2018.—WHEREAS, sub-section (1) of Section 10 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that—

- (i) a registered person engaged in the supply of services, other than supply of service referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act, may opt for the scheme under the said sub-section;
- (ii) a person who opts for the said scheme may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II to the said Act), of value not exceeding ten

percent. of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher;

AND WHEREAS, clause (a) of sub-section (2) of Section 10 of the said Act provides that the registered person shall be eligible to opt under sub-section (1), if, save as otherwise provided in sub-section(1), he is not engaged in the supply of services;

AND WHEREAS, rendering of services as part of the savings and investment practice of business, by way of extending deposits, loans or advances, in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, is resulting in their ineligibility for the aforesaid scheme, causing hardships to a lot of small businesses and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of Section 10;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 172 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 and in supersession of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2017, No. 01/2017-State Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* No. EXN-F(10)-39/2017, dated the 18th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the State Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that the value of supply of exempt services by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount, shall not be taken into account—

- (i) for determining the eligibility for composition scheme under second proviso to sub-section (1) of Section 10;
- (ii) in computing aggregate turnover in order to determine eligibility for composition scheme.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

**In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)**

Shri Om Prakash s/o Shri Nokh Ram, r/o Village Neen, P.O. Durgapur, Tehsil Suni, District Shimla.

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Whereas Shri Om Prakash s/o Shri Nokh Ram, r/o Village Neen, P.O. Durgapur, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court

of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name/date of birth of his/her son named—Chanchal Kumar s/o Shri Om Prakash s/o Shri Nokh Ram, r/o Village Neen, P.O. Durgapur, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Neen, Tehsil Sunni, District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of birth
1.	Chanchal Kumar	Son	23-04-2001

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to entry the name/date of birth of above named in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Neen, Tehsil Sunni, District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 11-02-2019 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.*

CHANGE OF NAME

I, Romesh Chand s/o Shri Beli Ram, Village Baddu, Post Office Dabhla (Dabla), Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.), Pin Code 174021, have changed my name from Romesh Chand to Ramesh Chand.

ROMESH CHAND
*s/o Shri Beli Ram, Village Baddu, Post Office Dabhla (Dabla),
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) Pin Code 174021.*

